Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 16 अंक 08 30 अगस्त 2016 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

धर्म बनाम राजनीति

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

कभी भारतीय शिक्षा, न्याय प्रक्रिया का विश्व लोहा मानता था, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व ज्ञान कुंज थे । राजनीति तब भी होती थी । राजे-राजवाडे तब भी थे लेकिन तब शिक्षक को उच्च स्थान दिया जाता था। चाणक्य जैसे गुरू को सम्राट तक सर झुकाकर चरण स्पर्ष करते थे लेकिन राजनीति और समाजिक तानाबाना अपनी-अपनी महता रखते हुये भी एक-दूसरे में दखल अन्दाजी नहीं करते थे । शायद यही बेहतरीन समाज की परिकल्पना को साकार करता था । आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि विपक्षी पार्टीयां केवल विरोध के लिए हर कार्यों में बाधा डाल रही हैं । ऐसा भी नहीं कि सरकार हर काम अनुचित ही कर रही हो । वास्तविकता यह है कि आज राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि किसी को राजनेता कहना मानस को गाली देने के बराबर है। जीवन के हर छोटे बडे पहलू में राजनेता अपनी गंदी सोच का पदर्शन करता हैं।

राजनीतिक के पर्दा पर्ण के लिये आज पूर्ण विश्व इसी संदर्भ में चिन्तत है । अमेरीका जैसा देश चर्च और राज्य दोनों को अलग कैसे रखा जाये के लिए संघर्षरत है । आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम समुदाय की सलिप्तता की बजह से करीब पूर्ण विश्व मुस्लिम समुदाय से नफरत के कगार पर पहुंच गया है । अकसर कई देशों के राजनेता पूर्ण समुदाय पर प्रतिबंध लगाने को अग्रसर है । जापान में मुस्लिम कहने पर कोई मकान किराए पर नहीं देता, कुछेक देश मस्जिद पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयासारत हैं। समाज को बांटने वाली यह नफ्रत कहां से आ गई । इसलिए स्टेट संस्था केवल हिन्दु, क्रिश्चन ही नहीं, मुस्लिम की भी दुश्मन हैं । आए दिन शिया-सुन्नी विवाद । यही नहीं जहां मुस्लिम अल्प संख्या में है वहां उन्हें कोई पसन्द नहीं करता, जहां बहु गिणती हो जाती है वहां वह दुसरों का जीना मुहाल कर देते हैं । कश्मीर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

राजनैतिक सत्ता के लिये चल रहे खेल के तहत जम्मु-काश्मीर में एक खतरनाक पाक आंतकी बुरहानवानी की सुरक्षा बलो के साथ 4 जुलाई को मुठभेड में मारे जाने पर राज्य में पूणतय अराजकता का माहौल बना हुआ है और लगातार डेढ महिने से कर्फ्यू लगाकर भी हालात पर नियंत्रण नही किया जा सका । दंगों के दौरान 20 निर्दोष व्यक्ति व सुरक्षा सैनिक मारे गये और करोडों की संपत्ति का नुकसान हो गया हालात पर नियंत्रण करने वाले सुरक्षा सैनिकों को राजनेताओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है । यहां तक कि सरकारी हस्तपालों में दाखिल जख्मी सुरक्षा बलों के सैनिकों पर भी उग्र भीड द्वारा हमले किये जा रहे है। प्रदेश में अराजकत्ता, आगजनी व नरसंहार की घटनाएं प्रतिदिन बढ रही है । प्रदेश में पिछले सप्ताह से 96 सुरक्षा सैनिकों सहित 200 से ज्यादा व्यक्ति दंगों में जख्मी हो गये है और हिंसक भीड द्वारा पुलिस संस्थनों, 3 सिविल प्रशासनिक अधिकारियों के निवास, एक पीडीपी विधायक, अनेको वाहन तथा बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी गई । दंगों के कारण पवित्र अमरनाथ यात्रा भी दूसरे दिन भी स्थागित रही और इसमें लगे अधिकांश पुलिस और सुरक्षा सैनिकों सहित 200 से अधिक व्यक्ति घायल हुये। आज हालात ये है कि राज्य में लगभग हर स्थान पर पाकिस्तानी आतंक का साया छाया हुआ है लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री महोदया लगातार पिस रही जनता से शांति बनाये रखने की अपील कर रही है । पहले यहां पर हिन्दु टारगेट हुए अब सिखों की बारी है । यह सब राजनीति का ही घिनौना खेल है । यह धर्म के ठेकेदार अल्प ज्ञानी करवा रहे हैं।

महर्षि अरविन्द ने कहा कि हिन्दुओं से एकता सम्भव नहीं क्योंकि कुरानमत मित्र मानने को सहन नहीं करता । सरकार बल्लवभाई पटेल - पाकिस्तान मिल जाने के बाद भी इनके नेता

शेष पेज–2 पर

’k"k i`:t &1

फूट के बीज बो रहे हैं। डा0 भीमराव अंबेडकर - एकता असम्भव है इन्हें सभी को पाकिस्तान और वहां से हिन्दु, सिखों को भारत बुलाना चाहिए अन्यथा सामाजिक संस्था बनी रहेगी ।

श्रीमती ऐनी बेसेंट - गैर मुस्सलमों से हद तक नफरत है ।

स्वामी रामतीर्थ - अधिकांश समुदाय गैरो को काफिर मानता है।

भारतीय संविधन धर्मनिरपेक्ष है । नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है ।

हमारे देश की बहुत बडी विडंबना रही है कि यहां पर अलग-अलग धर्मो को अपनी-अपनी आजादी मिली है इसलिये अकसर धर्म के नाम पर उपद्रव फैलाये जाते है । जम्मू काश्मीर में संविधान की धारा 370 के तहत दुसरे प्रांतों के लोग न तो यहां के बंसिदे हो सकते है और ना ही कोई जायदाद खरीद सकते है । 1947 से 1950 के दौरान पाकिस्तान से आये लोगों को अभी तक कोई वोट का अधिकार नहीं मिला है । इसलिये धारा 370 के तहत लगी पाबंदीयों को हटाया जाना राष्ट्रहित में है। इसी प्रकार पूरे राष्ट्र में देश की एकता और अखंडता को मध्यनजर रखते हुये एक समान सिविल कोड होना चाहिये।

यह भी दुर्भागयपूर्ण है कि राष्ट्र में आरंभ से ही सत्ता संचालन में जातिय व धार्मिक गतिविधियों का हस्ताक्षेप जारी रहा है जिस पर किसी भी सरकार व राजनैतिक दल ने आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत नही समझी। स्वतंत्रता पूर्व ही दलगत व स्वार्थी नेताओं द्वारा भारतीय नागरिकों तथा राष्ट्र की संस्कृति के विरूद्ध मुस्लिम अंहिसा तथा खतरनाक इस्लामी तत्वों को बढावा दिया गया। पिछले 1000 वर्षों से इसरायली तथा हिन्दु इस्लामिक आक्रमण व अंहिसा का शिकार होते रहे है । यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जिन्हा तत्कालीन ब्रिटिश शासन व प्रभावशाली राजनीतिज्ञों से सांठ-गांठ करके अभाजित राष्ट्र को 2 हिस्सो में बांट कर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुये जिसका नतीजा आज सभी को भुगतना पड रहा है। पाकिस्तान में आज भी हिन्दुओं के साथ पक्षपात व भेदभाव किया जा रहा है । आजादी के समय पाकिस्तान में हिन्दुओं व सि1खों की जनसंज्या लगभग 10 प्रतिशत थी और अब यह केवल 1 प्रतिशत रह गई है । सवाल यह है कि इतने लोगों को कहीं भगा दिया गया या 1971 के भारत-पाक युद्ध की आड में कत्ल कर दिया गया । एक अनुमान के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान में केवल इस एक वर्ष में 2.4 मिलयिन हिन्दुओं का कत्ल व 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया । कनाडियन हिन्दु एडवोकेशी ग्रुप के निदेशक के अनुसार विभाजन के बाद आज भी असुरक्षा के कारण भारत में पाकिस्तान से आये हुये लगभग 100 हिन्दु परिवार आश्रय लिये हुये है जोकि धार्मिक कटरवादी दुरभावना का स्पष्ट परिणाम है ।

राष्ट्र की जनता तुष्ट राजनीति से उत्पन्न जातिय दंगों ---1947 के विभाजन के दंगे, वर्ष 1895 व 1899 के काजू हुमलाई व शिवा1सी दंगे, कोलकता में 1946 के ‘डायरकेट एकसन डे’ के दंगे, 1927 के नागपुर दंगे, वर्ष 1957 केरामानन्द दंगे, 2006 के महाराष्ट्र में दलित विरोधी दंगे, 2002 के बेस्ट बेकरी दंगे, वर्ष 1984 के सिज्ख विरोधी दंगे, 1989 के वाराणसी के हिन्दु-मुस्लिम दंगे, 1989 के सिल्क सिटी भागलपुर के जातीय दंगे, वर्ष 1992-93 के मु6बई के हिन्दु-मुस्लिम दंगे, वर्ष 2002 में गुजरात में हुये हिन्दु-मुस्लिम दंगों से उपजा गोधरा कांड, वर्ष 2012 के आसाम में हुये भारतीय बोडो व बंगलादेश के प्रवासी मुस्लमानों के जातिय दंगे, हाल ही के मुम्बई, आसाम व मथुरा के जातिय-धार्मिक दंगों के खतरनाक उपद्रवों, व तसुन्दर आध्रप्रदेश 1991, 1996 के भडानी तोला (बिहार) नरसंहार, 1997 के मालव लायु (तमिलनाडू) नरसंहार, 1997 की मुम्बई रामाबाई हत्याएं, 2008 में कर्नाटक हिंसा, केरल-मुथंगा 2003 दंगे, महाराष्ट्र-खैरलांजी 2006 नरसंहार, जावखेडा महाराष्ट्र 2014 हत्याकांड आदि हिंसक जातिय उपद्रवों के नुकसान से जनता अभी तक उभर नही पाई है लेकिन सत्ता आसीन नेताओं का राष्ट्र में अमन चैन कायम करने का कोइ प्रयास नजर नही आता और वोट बैंक की राजनीति निरंतर जारी है।

हरियाणा जैसे छोटे से शांति प्रिय प्रांत में भी जाट समुदाय द्वारा अपने हितों के लिये किये जा रहे शांति पूर्ण आंदोलन को भी सोची-समझी राजनीति के तहत हिंसक बना दिया गया जिसमें कई निद्रोष नौजवान मारे गये व करोडो की नीजि व सार्वजनिक सम्पति नष्ट कर दी गई। सता दल के एक सांसद द्वारा सरेआम एक विशेष जाति के खिलाफ भंडकाव बयान देकर समाजिक भाईचारा खराब किया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार इस संवेदनशील विषय पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। राज्य सरकार धर्म की राजनीति में हो रही बेवजह घुस्पैठ को रोकने में नाकाम शाबित हो रही है, अब तो विधान सभा क्षेत्र में भी संतों के प्रवचन होने लगे है। हाल ही में अगस्त के अन्तिम सप्ताह में हरियाणा सरकार द्वारा राजनीति में धार्मिक सांझेदारी के दो महत्वपूर्ण मामले उजागर हुये है । प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के एक धार्मिक डेरे को खेलो के प्रोत्साहन के नाम पर 50 लाख रूपये की राशि जारी की गई जबकि इस डेरे का प्रमुख आरम्भ से ही राजनैतिक सुर्खियों में रहा है और इसके विरूद्ध हत्या, महिलाओं के साथ यौन-शोषण व बलात्कार के कई सगीन अपराधिक मामले न्यायलय में लम्बित है । एक ओर घटनाक्रम में सरकार द्वारा एस्मबैली में प्रवचन के लिये धार्मिक गुरू दीनानाथ बतरा को आंमत्रित किया जा रहा है । धर्म गुरू से प्रवचन करवाना तो अच्छी बात है लेकिन विधान सभा में धार्मिक प्रवचन करवाया जाना एक अनुचित प्रथा के इलावा संविधान द्वारा प्रदत धर्म-निरपेक्षता के भी विरूद्ध है। क्या प्रवचन सुनकर नेताओं का दिमाक साफ हो जायेगा। पंजाब जैसे शांतिप्रिय व गौरवशाली प्रदेश को भी सुनियोजित राजनीति के कारण एक दसक तक आंतवाद से जुझना पडा जिसमें प्रदेश की जनता को पुलिस प्रशासन की जातियों को सहन करने के साथ अनेकों नौजवान बेमौत मार दिये गये।

एमेनसटी इन्टरनैशनल और मानव अधिकार वाच की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र में 2005 से 2009 के बीच औसतन 130 व्यक्ति प्रतिवर्ष जातिय व धार्मिक हिंसा का शिकार हुये जो कि यथावत जारी है। इन पांच वर्षों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक धर्म से संबधित घातक वारदात हुई जबकि मध्यप्रदेश में हर एक लाख की जनंसज्या के पिछे प्रतिवर्ष सबसे अधिक धार्मिक हिंसा की घटनाएं हुई। वर्ष 2012 में पुरे देश में विभित्र धार्मिक विवादो से हुये दंगों में 97 व्यक्ति मारे गये जबकि गत वर्षो में विश्व की 1 लाख की जनसज्ंया में आर्तरिक हिंसा के कारण हुई वार्षिक मृत्युदर 7.9 है। आंध्रप्रदेश, बिहार, तमिलनाडू, राजस्थान आदि राज्यों में भी राजनेताओं के निहित स्वार्थों के कारण काफी जातीय-धार्मिक विवाद होते रहे है। आन्ध्रप्रदेश में अगस्त 1991 में हुये दलित विरोधी दंगों में उग्र भीड द्वारा 80 व्यक्ति मारे गये जिसमें बाद में 21 उपद्रवियों को उमर कैद व 35 को गंभीर सजा सुनाई गई। विहार में वर्ष 1996 में रणवीर सेना द्वारा 20 निरदोष व्यक्तियों की हत्या की गई। इसी प्रकार तमिलनाडू में वर्ष 1997 में दलित व अन्य जातियों के संघर्ष में 6 व्यक्ति मारे गये। कर्नाटक राज्य में वर्ष 2000 में गैर कत्रड भाषी

समुदाय के साथ हुये धार्मिक दंगों के कारण हुये एक बडे जातिय उपद्रव में 8 व्यक्ति मारे गये और अनेको घायल हुये। इन सब के बावजूद भी जातिय व धार्मिक विवादो से हुई घटनाओं को रोकने में केन्द्रीय व राज्य सरकारे नाकाम सिद्ध हो रही है और राजनीतिक वोट बैंक की नीति यथावत जारी है। आजकल केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई गौ संरक्षण-सुरक्षा नीति से भी राजनैतिक रसूख व प्रभावशाली व्यक्तियों को अपनी दबगता दिखाने की छूट मिली हुई है। प्रभावशाली नेता गौ सुरक्षा के नाम पर एनजीओ बनाकर समाज में अपना दबदबा बनाने में प्रयासरत है। इस व्यर्थ की मुहिम को नियंत्रण किया जाना चाहिये और गौधन के वास्तविक संरक्षक-किसान व काश्तकार की अवस्था को अगर सुधार दिया जाये तो स्वतः ही गौधन सुरक्षित हो जायेगा और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने पर भी अंकुश लग जायेगा।

इन्सान घर बदलता है, लिबाज बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान ज़्यों रहता है ज़्योंकि वह खुद को नही बदलता है। 'मिर्जा गालिब ने कहा था 'उमर भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा।' मैदान का हारा हुआ पुनः प्रयास करे, जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ कभी नही जीत सकता। आपका आतमविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ट पूंजी है। तू छोड दे कोशिशे इंसानों को पहचानने की यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नाकाब है। अपने गुनाहों पर सौ परदे डाल कर हरके कहता है 'जमाना खराब है।' पाकिस्तान का अस्तित्व जिन्हा की परिकिल्पना थी कि राष्ट्र निर्माण में भाषा-धर्म ओर एक समान शत्रु प्रमुख थे। पाकिस्तानी का अर्थ था उर्दू बोलने वाला मुस्लिम और भारत से नफरत करता है।

महात्मा गांधी का माडल नवांमेषी और मौलिक था। अन्य भारतीय विचारक और संगठन अपने दृष्टीकोण में अमौलिक थे। हिन्दु महासभा हिन्दु भारत की बात करती है। भारतीय राजनीतिज्ञों ने यूरोपीय राष्ट्रो को खुद सांझी भाषा आधार पर संगठित होते देखा था और वे ऐसा ही चाहते थे। पुरे भारत में हिन्दी थोपने हेतू एम एस गोवलकर और राम मनोहर लोहिया शामिल थे। वे पाकिस्तान की भारतीयों के प्रति नफरत के प्रति उतर में भारतीयों से भी यही चाहते थे। आजादी से अब तक एक समान भाषा, एक समान शत्रु के आधार पर एक जुट करने का पक्षधर रहे है लेकिन अब तक इस परिकल्पना का विरोध हो रहा है और धर्म को राज्य से मिलाने से रोक रखा है। नियमित ओर स्वतन्त्र तरीके से बहुदलिय चुनाव इस देश की एकता-अखंडता और अनेकता में एकता बेजोड है। अडोस-पडोस में कट्टर पंथी है लेकिन हम अपना धर्म-निरपेक्ष अस्तित्व बनाये हुये है। कई मुद्दों पर संकीरणता आज भी इस तान-बाने को प्रभावित करती है जैसे खेल के मैदान में चैन प्रक्रिया जाति, क्षेत्रिय इत्यादि आधार पर होती है, जिसका खमियाजा इतने बडे राष्ट्र की बेइगाति का वाईस है। हाल ही में रिओ ओलपिंक में प्रदर्शन नाकाबिले जिक्र की हद तक है। अगर समय रहते खिलाडियों के चयन व प्रशिक्षण में राजनीति को नाकार कर पारदर्शिता बरती जाती तो खिलाडियों का बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता था। अभी भी इनकी गलतियों पर मनन करने का वक्त है और अभी से जापान के लिये खिलाडी चयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया बिना लाग-लपेट करे, जापान में तिरंगे का परचन लहरायेगा और राष्ट्र को नाम और शोहरत लेकर आयेगा।

आज की राजनीतिक पार्टीयों में कइयों कि धरातल ही धर्म है। कई पार्टीयां वोट बैंक की खातिर भारत की एकता और अखडता को तहस-नहस कर रही है जिसको रोकना नितान्त जरूरी है। 'धर्म से आजादी और धर्म की आजादी' दोनों ही भारत की एकता-अखंडता को अनेकता में एकता पालने में सहायक होगें। अपनी आस्था कायम रखने हेतू दूसरों का गला काटना जरूरी नहीं। इसका आधार है दूसरों से वार्ता करें, उन्हें समझे, अपनी समझायें। सेना में सभी भारतीय है। उनके साथ मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा साथ चलता है। कई बार एक छूट्टी पर जाता है तो दूसरे धर्म का व्यक्ति दोनों की पूजा-अर्चना में बाधा नहीं आने देता। इसी तर्ज पर आम नागरिक भी कर सकते है। हरेक को धम्र की आजादी है लेकिन सरकार द्वारा थोंपा जाना अमान्य होगा। सभी धर्मो को दूसरे धर्म की आजादी की पूरी छूट देना सरकार का उतरदायित्व है, किसी को दबाना उचित नहीं। हज पर जाना उसका मौलिक अधिकार है लेकिन दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी पर हांडी उत्सव, अमरनाथ यात्रा हिन्दुओं का मौलिक अधिकार है और ऐसे कार्यों को सज़्मपन्न करने में दूसरों का सहयोग देना होगा जिससे शांति और सौहार्द बनेगा।

हज यात्रा पर सबसिडी और अमरनाथ यात्रा में बाधा। दुर्गा पूजा में मुर्ति ढके और मस्जिद से अंजान हेतू स्पीकर, केवल समाज को फाडने में सहाई होगी - सौहार्द नहीं। भारत के बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे है जहां पूजा अर्चना दूसरे धर्म के अनुयायी ही करते हैं। अमरनाथ के पूजारी मुस्लिम है। दशहरा पर बनने वाले पुतलों के कारीगर और दुर्गा व गणेश की मुर्तिया बनाने वाले कारीगर भी वहीं हैं किसी को अब तक ऐतराज नहीं तो फिर असहक्षुणता ज़्यों, इसकी जड को खोदे और निदान करें। शांति ओर भाईचारा स्वतः कायम हो जायेगा। वोट बैंक की राजनीति सत्ता पर बने रहने हेतू किसी की जायज-नजायज बात मानने हेतू दूसरें का गला काट रही है। विपक्ष सदा विरोध में ही सिर न उठाये, बल्के एकता-अखंडता के लिये दोनों पक्षों को समझाये, सरकार को सीख दे और उचित कार्यों में सहयोग भी नितांत जरूरी है जिसकी आज बहुत कमी है। समाज जाति-पाती के बंधन में विभाजित हो रहा है जोकि किसी के भी पक्ष में उचित नहीं है। जनता भी ऐसे राजनीतिज्ञों का बहिस्कार करें जिससे अवश्य ही समाज सुधार होगा। आज की राजनीति इसके विपरीत आंतकवाद, नस्लवाद व अलगाववाद को बढावा देने में संल्पित है। भोलीभाली जनता अपना नफा-नुज़्सान जाने बिना उनके पीछे लग जाती है। सरकार सरकारी संपतियों का नुकसान होता है जो बिना सोचे समझे की देन है, इसकी भरपाई सरकार को नही हमने ही करनी है। सरकार यह घाटा कर बढाकर ही पूरा करेगी। एक वृक्ष को पालने में कम से कम 10 वर्ष लगेत है, एक दिन के आंदोलन में सैंकडो नष्ट कर दिये जाते है। वातावरण का नुकसान इंसानियत का अपना है। राजनेता का कुछ नही गया वह तो अपनी रोटियां सेक गया। अकसर सुनने को मिलता है 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना' लेकिन आज वास्तविकता यह है कि 'मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना' हर धर्म प्यार और भाईचारें की बात करता है फिर यह अलगाववाद कहां से आया।

आओं हम सब मिलकर आहवान करें कि हम सब भारतीय हैं, अपने धर्म को मानते हूये 'जियों ओर जीने दो' की अवधारणा कायम करें, जो विश्व के लिये अनुक्रणीय होगी और भारत प्रगति के परचम लहरायेगा। धर्म और राज्य पूरक बनकर रहेगें, एक-दूसरे के रक्षक बनेगे भक्षक नहीं। एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदार बन कर राष्ट्र की सुरक्षा, अंखडता व आन-बान को कायम रखने हेतु एक जूट होकर कार्य करने की कसम लें।

डा0 महेन्द्र सिंह मलिक
आई.पी.एस., सेवानिवृत,
प्रधान जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

जिन्दगी को लीलती जहरीली शराब

– डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (पूर्व सांसद)

जहरीली शराब से एक बार फिर कहर बरपा है। हाल ही, 16 जुलाई 2016 को, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या (28) में लोगों की मौत के बाद फर्रूखाबाद में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। ध्यातव्य है कि 4 अप्रैल, 2016 को राजस्थान के बाड़ेमर में भी हथकढ़ जहरीली शराब पीने से 17 से ज्यादा मरे थे। साल–दर–साल, एक के बाद एक, राज्यों में अवैध शराब के कारण मौतों की घटनाएं होती रहती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के आंकड़े दिल–दहलाने वाले हैं। देश में, दस वर्षों (2004–2013) में ऐसी कुल मौतें 9,986 (7,340 पुरूष 2,646 महिला) रिकार्ड हुई। सबसे ज्यादा मौतें 1561 (1081 पुरूष 480 महिला) तमिलनाडु में हुई। पंजाब में 1349 मौतें (1018 पुरूष 331 महिला) हुई। कर्नाटक में 1332 (899 पुरूश 433 महिला) वेस्ट बंगाल में 1093 (707 पुरूष 386 महिला) और गुजरात में 882 (642 पुरूष 240 महिला) मौते दर्ज हुई। ''प्रशासन अनुकम्पा राशि हर मृतक परिवार को देकर, अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। परंतु, क्या इससे वेदनासिक्त परिवारों की क्षतिपूर्ति हो सकेगी? यक्ष प्रश्न है कि यह कैसे सुनिश्चित हो कि भविष्य में ऐसी दुखांतिका न घटे। पूर्ण शराबबंदी तुरंत लागू हो।''

ज्ञातव्य है कि गांधी जी ने कहा था, ''मैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानता हूं, क्योंकि यह उक्त दोनों बुराइयों की जननी है। यदि मुझे एक घंटे के लिए समूचे भारत का डिक्टेटर (अधिनायक) बना दिया जाए तो मैं पहला काम यह करूंगा कि शराब की तमाम दुकानों को बिना मुआवजा दिये बंद करा दूं।'' यह घोर विडंबना है कि कल्याणकारी राज्य होने का दम भरने वाली सरकारों के लिए शराब राजस्व जुटाने का बड़ा जरिया बन गई है। इस बात की होड मची है कि कौन शराब कारोबार से कितना ज्यादा कमाता है। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि राजस्व जुटाने का यह माध्यम जानें लील रहा है। सरकार एक तरफ तो नशे के खिलाफ अभियान चलाती है, दूसरी तरफ आबकारी विभाग ही शराब की खपत बढ़ाने के टारगेट देती रहती है। राज्य में जिस तरह से गली–गली में शराब की दुकानें नजर आ रही है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने और शराब के सेवन को प्रोत्साहित कर रही है और शराब की कमाई से खजाना भर रही है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के 47वें अनुच्देद में भी कहा गया है कि सरकार चिकित्सकीय उद्देश्य को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थों और नशीली चीजों का उपयोग निषिद्ध करने के लिए कदम उठाएगी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में सुनाए एक फेसले में भी कहा था कि वक्त की पुकार है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें संविधान के 47वें अनुच्छेद पर अमल करें।

शराब की खपत को धीरे–धीरे घटाना सरकार का कर्तव्य है। जाहिर है कि राज्य सरकारें संविधान में वर्णित अपने कर्तव्य के विपरीत आचरण कर रही है। राजस्थान में तो काफी समय से शराबबंदी की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश में शराब बंदी की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक आबकारी विभाग और पुलिस महकमा नियमित रूप से अवैध शराब निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस तरह के हादसों को रोकना मुश्किल है। परिवारों की तबाही को रोकने और लोगों को मरने से बचाने के लिए राज्यों को अपने संवैधानिक दायित्व की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शराबखोरी बढ़ाकर लोगों को मौत की तरफ धकेलने वाली सरकारें कल्याणकारी कैसे मानी जा सकती हैं?

शराब दुखांतिका के इन हादसों में ज्यादातर गरीब लोग मारे जाते हैं। वे सस्ती शराब के चक्कर में खराब तरीके से बनी अवैध शराब खरीद लेते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। देसी शराब और भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब के दाम अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सड़क और भवनों के निर्माण व कारखानों में लगे गरीब दिहाड़ी मजदूर अपने शारीरिक श्रम की थकान मिटाने के नाम पर आसपास में उपलब्ध सस्ती अवैध शराब पीते हैं। इस कारोबार में लगे लोगों को न तो आदमी की जान की परवाह है और न कानून का खौफ। वे अवैध शराब बनाने में रसायनों और रासायनिक खाद तक का उपयोग करते हैं। अवैध शराब के इस काले कारोबार में बच्चों समेत पूरे परिवार के परिवार शामिल रहते हैं। महिलाएं शराब लाने ले जाने और बेचने का काम करती हैं। जरायम पेशा कही जाने वाली कई जातियों के बहुत से लोगों ने इसे ही अपनी आजीविका का साधन बना रखा है। ज्यादा मुनाफा कम पूंजी की जरूरत, कच्चे माल की आसानी से उपलबधता, आबकारी व पुलिस विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार और इनके मामलों की अदालतों में सुनवाई में बरसों लगने के कारण इसमें जोखिम भी कम माना जाता है।

यह स्तुत्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार में 01 अप्रैल 2016 से देशी–विदेशी शराब के बेचने, रखने और पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद अब बिहार गुजरात, नागालैंड और मिजोरम के बाद देश का चौथा (ड्राई स्टेट) बन गया है। काश, अन्य राज्य भी पूर्ण शराबबंदी लागू करें। आज समाज को लीलते अवैध शराब के जहर से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाने की जरूरत है। यही समय है कि सभी स्तरों पर जागरूक होकर, इस नशे के जड़–मूल से उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर धावा बोला जाए, वरना पानी सिर पर से गुजर जाएगा। सरकार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया, सांसद, विधायक, पंच, सरपंच के द्वारा एकजुट होकर व्यापक सामूहिक अभियान और आंदोलन चलाकर ही इस जानलेवा 'नशे के दैत्य' पर काबू पाया जा सकता है।

अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए, सामाजिक जागरूकता और सरकार सक्रियता जरूरी है, परंतु सर्वोपरी है कि राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता। सामाजिक और गैर सरकारी संगठन भी नशा मुक्ति के लिए प्रयास करें।

यदि समय रहते इस पर प्रभावी रोक नहीं लगी, तो शरीफ आदमी का समाज में रहना दुष्कर हो जाएगा।

बुरी आदतों की कीमत दो बार चुकानी पड़ती है, एक बार जब आप उनके प्रभाव में आते हैं, दूसरी जब वह नुकसान पहुंचाती हैं। –अज्ञात

21- point program for waging war against poverty and boosting Indian economy

- R.N. Malik

Finally after two years, Honourable Prime Minister Sh Narinder Modi presided over the meeting of NITI AYOG on 28.07.2016 and asked the AYOG to prepare a 15 years Vision document (2016-30) coterminous with sustainable development. He did not set any development parameters or indices e.g. develop 50000 MW hydro power energy by 2030. He also stressed for bringing transformational changes instead of incremental reforms. He also asked the AYOG to prepare two sub-documents delineating action plan for 2016-19 and 2017-24 periods. It is not clear how much time NITI AYOG will take to prepare these documents. Dr Arvind Panagariya-Vice-Chairman asked for increasing the staff of AYOG to prepare the documents. My estimate is that NITI AYOG will take at least one year to accomplish the job. The vision document will encompass 3 Five Year Plans.

In order to prepare the precise road map for India's sustainable development, NITI AYOG should set the following three goals in its vision/front.

(a) Eradicate total poverty by 2030 and level the economic inequalities.

(b) To raise the human development index from 134 to 50th rank in the international table.

(c) To beat China in the economic race by 2030.

Poverty in India exists in two categories. (i) 300 million people (equal to the population of Europe excluding Russia) living below the poverty line as defined by World Bank. (ii) An equal number living above the poverty line by few notches called marginally poor. Lives of people in this category is also very harsh.

According to Jefferey Sachs, six keys to achieve aforesaid goals and bring prosperity are described below. GOI did not use these keys professionally and that is why India still carries the tag of being an underdeveloped country.

1. Massive infrastructure development in the right areas.
2. Drastic control over population explosion. We are adding one Australia every year and successive governments are very allergic to touch this issue.
3. Economic and administrative reforms as defined by World Bank.
4. Massive campaign for total sanitation.
5. Direct foreign investments (FDI).
6. To stop competitive populism practiced both by states and central government.

Government requires huge amount of money to achieve above six objectives. Accordingly a sound financial revenue model also needs to be designed or developed simultaneously. Economic conditions in China till 1976 (when Deng Xiaoping took over) were no better than India's. Now see the difference in the economies of the two countries. If China can rise like a phoenix, why cant India do the same now over a period of next ten years. Late President Lee Kuan Yiew also achieved something similar in case of Singapore.

The performance of NDA government during the last 2 years has been below the expectation of the aspirational and transactional youths because enough employment opportunities for them were not created. Accordingly popularity graph of the government is constantly on the decline notwithstanding the victory in recent Assam elections.

The Indian economy is not showing very good signs in spite of three fold crash in crude oil prices. The crude oil price has started rising gradually and it was $50 per barrel on 25.5.2016. It can upset the apple cart of Indian economy. 7.5% growth is invisible, non-inclusive and uninspiring. Rupee is unstable and wobbling. Exports are dwindling. Manufacturing and service sectors are showing notional growth. Agricultural growth is stagnant. There is no visible impact on poverty. 300million people are still wallowing in tear jerking deprivation.17 paisa hypothesis of Late Shri Rajiv Gandhi is still relevant in respect of MNREGA and distribution of food grains under Food Security Act. GST Bill is still hanging in the thin air. Indian Railways is still struggling below poverty line. Smart city program is likely to fail because allotment of Rs.500 crore per city per year will hardly construct 2kms of metro rail.Innovative programmes like Skill India or Digitalise India have not picked up the required momentum so far. Ease of doing business has improved only by 10 points and India now occupies 126th place. POSCO (A Korean company, desirous to invest Rs 60000 crores) is sitting idle in Odisha for the last 12 years without getting the promised land. Therefore the foreign investor is still very shy to invest in India. The quality of education in private Engineering and Medical Institutes has touched a new low as these are being run like commercial shops. The target of developing 1.75 lac MW of renewable energy is still a far cry.

But one must admire the herculean effort of the Honourable Prime Minister to market India in World capitals. National Highway Authority (NHAI) and Coal India Limited (CIL) are doing wonderful jobs. Ministry of Environment has also been very quick in clearing the projects But three essential Expressways namely Noida-Balia, Lucknow-Surat and Patna-Paradip have not been taken up so far. Finance ministry also was able to limit the Fiscal Deficit to 3.86% of GDP. Efforts to give food subsidy in cash to the poor are admirable but unfortunately State Govt's. are not responding for capricious reasons.

Taking a holistic view of the prevailing situation, I suggest below a 21-point program which should be the hallmark of the proposed roadmap.

1) Solar revolution in the country is waiting to happen. We talk of solar energy development only for the generation of power and forget two other equally important aspects i.e. Solar

cooking and Water heating. One order of government for compulsory solar cooking in the messes of Armed Forces, Police Lines, Hostels, Hospitals, Hotels, etc., compulsory use of Solar water heaters on the residential buildings, compulsory provision of roof-top solar power panels in institutes and houses with size 500 sq. yards or more is enough to revolutionize the economy and provide vast employment opportunities to the youth. Solar cooking can save huge amount of cooking gas.Development of solar energy provides the lowest hanging fruits

2) The issue of population control has remained thoroughly untouched. We are still adding one Australia to the national pool every year. Social and economic conditions within the country will be totally paralysed if the problem of population explosion is not tackled immediately. Therefore a soft but aggressive program needs to be taken up to educate and sensitize people for control of population particularly in five Bimaru states. Presently,the greatest danger to India's socil and economic fabric is from the explosion of Population Time Bomb that will explode around 2025 to cause demographic disaster. Only the implementation of one child policy can save the situation

3) There is no synergy in the development activities undertaken by government of India and the states. There are serious fault lines between the Centre and the states where the governments belong to different political parties. Therefore the PM has to make earnest efforts to captain the team of State Chief Ministers and involve them in development projects. The wonderful "Swach Bharat Abhiyan" failed and became a big joke because Government did not sensitise the Chief Ministers to implement this program seriously. India is not United States of India and Chief Ministers cannot be allowed to treat the states as their personal fiefs. Till now the honourable PM has not convened even a single meeting of Chief Ministers to suggest them the development goals for their respective states. There is no way of berating the laggard states in the matter of development.

4) (a) The progress in the field of water resources and hydro power development is only notional. The issue of suicides of farmers particularly in Maharashtra and other water starved states is directly related to this issue. China completed the massive 3-Gorges Dam Project in 6 years. Its power generation capacity of 18200 MW is 2.5 times the capacity developed by NHPC in 35 years River Brahmaputra alone can yield 1.0 lac MW of hydropower. The prosperity of hill states depends largely on hydropower capacity. Flood waters of River Yamuna and Ganges still flow to the sea unutilised for want of storage dams in the basin. Untapped hydro-power potential in various hill states amounts to 50000 MW which can be easily exploited over a period of 8 years.

(b) There should be a massive campaign for water harvesting projects in different states particularly in central India where farmers suicides are maximum.

5) Country size states of UP and Maharashtra cannot be run efficiently by one Chief Minister and these need to be split into smaller states. The right size of a State should be equal to the area of 15 constituencies of MPs. Poverty of U.P will never go till the State is split into three. Setting up 30 new townships (along with industrial states) to act as sub-capitals in various states will provide lot of employment opportunities and improve governance in the states.

6) Earnest efforts be made to develop horticulture and dairy development in seven N-E states. These lush green states have very large potential to bring fruit and milk revolution in India. Presently cattle wealth in these seven states is very scarce.

7) The banking system is under great stress with Rs 3.35 lac crore NPAs .Many states like West Bengal, Punjab, and Haryana are under severe debt traps. The debt on the head of West Bengal Govt. is Rs 3.05 lac crore. Debt obligations are seventy seven percent of the revenue generated. H.P Govt takes loan from one bank to pay off the debt of the other. Who will pay these mounting debts? The situation has become explosive as three nationalised banks have become red and bad loans of Rs.1.14 lac crore have been written off. Therefore Goi needs to sit with states to work out a policy to reverse these trends. Ten PSU banks have shown a net loss of Rs. 20 000 crore in the January- March quarter of 2016. The banking system may face a paralytic situation at any time. The writing on the wall cannot be ignored any further.

8) Indian Railway is crying to become a major engine of growth in Indian economy. About 375 projects are languishing for want of money. Some projects are languishing for the last 15 years.60% railway tracks are still underutilized. The answer to all these problems lies in allowing the states to run railway service within their respective territories on a gradual basis. IR should run only the inter-state trains. This one step decentralization will revolutionize the Indian Railways.Private sector needs to be roped in to run trains on grossly under-utilised tracks like Sirsa to Gurgaon.

9) a) There is not a single institution/ university or scientific research which can pass muster with renowned universities of the world. One at Bangalore leaves much to be desired. Other institutions under CSIR (e.g. Botanical Garden Research Institute at Thiruvananthapuram) are struggling because of red-tapism. Over-crowding in AIIMS Delhi has to be seen to be believed. Tata Institute of Fundamental Research is the only exception in this regard. Rajiv Gandhi Education City near Sonipat was a good idea to set up such institutes but it could not take any shape. Therefore a series of world renowned scientific institutes need to be set up in India on an urgent call.

10) a) Medical Health care has become a big issue for every citizen. Government hospitals do not provide quality treatment. Private hospitals mercilessly fleece the patients. India has already become the diabetic capital of the world. ICMR says that 14.5 lakh new cases of cancer are sprouting every year. Mushroom growth of private institutions (both Engineering and Medical) are bringing out sub-standard products. The common refrain in villages is "Save us from the loot of private doctors and private schools and ensure regular

supply of canal water. Rest we will do". World Bank rightly says that India suffers from two kinds of poverty i.e. financial poverty and poor delivery of service form the infrastructure already created.

b) Quality standards of Engineering and Medical education in many universities and colleges is deteriorating beyond imagination. A policy to allow the entry of capable students only in such institutes will stem the rot.

11) Make special efforts to ensure rapid exploration of hydrocarbons within the country. There has not been any significant discovery of oil or gas during the last 15 years in spite of auctioning the exploratory blocks. ONGC Videsh too has not made any significant contribution. Cairn India has shown vast potential of oil in Rajasthan and presence of ONGC is still not there.

12) Swach Bharat Abhiyan is a wonderful program. But it is being implemented by the states with a very casual approach. It should have included two more sub/ programs of providing 100% sewerage system and solid waste management for all the towns by 2019. Every drop of treated waste waters should be recycled for agricultural use.

13) Very little effort is being made to exploit the potential of tourism in hill states. These states could have been developed into new Switzerlands of India by improving their roads and developing more hot spots of tourist attractions. Reduction of road distances between important cities by constructing tunnels will attract more tourists.

14) FCI and state agencies need to revamp its system of collection and distribution of food grains. There are ways by which loss of food grains during storage and distribution can be minimised significantly.

15) There is significant pilferage / leakage of funds in MNREGA and Food Security Program. Every penny needs to be saved from these programs to be used for big ticket infrastructure projects.

16) The debt on the heads of power utilities in most of the states is rising day by day because states are least bothered to reduce the power theft and do not compel people to pay the electricity bills because of vote bank politics. Likewise many PSU's are also in the red. Air India is under a debt of Rs. 35 000 crore and it is still mounting. Therefore the government has to take an urgent call to bring financial discipline and reverse this trend.

17) Make in India program will succeed only if following two significant steps are taken

a) Improve the parameter "Ease of doing business in India" from 126th to 50th position by announcing a slew of policy directives.

b) Set up Modern Industrial Parks/SEZ's of international standards along coastal areas.

If these two steps are taken in right earnest, foreign investors will come running to India.

18) A new Ministry should be set up to ensure recycling of all types of waste products being generated in the country. This Ministry will work on the principle of converting waste into a basket of wealth.

19) India should invest in African countries in a big way like China. This investment will give immense benefits in improving the lot of people of Africa, employment opportunities to Indian youth and import of vast mineral resources in a bonafide manner.

20) a) Time has come when there should be a network of Expressways (besides the dedicated railway freight corridors) for quick transport of freight by trucks from interior to the ports. Noida- Balia Expressway conceived by Maywati Government was a wonderful idea and should not have been abandoned by the successive government. Some of the Expressways could be Amritsar-Ahmedabad, Delhi-Patna-Paradip, Allahabad-Vizag and Allahabad-Surat etc.

b) All the district towns and mega cities of India are riddled with two very serious and common problems.

(i) Traffic congestion

(ii) Haphazard growth

In fact most cities in India are in the process of urban decay because of these two fundamental issues. Problem of traffic congestion can be solved by building a series of elevated tracks and metro lines. Building circular road/bypass and shifting some of the offices from the interior along the circular road will facilitate decongestion of the city it will be better if a national policy is brought into play to decongest all the cities of India. For example, Mumbai will be decongested only if all the Govt. offices are separated out and rebuilt into a new township. Problem of haphazard growth can be tackled by a strong will power of the state Govt. Therefore adequate funds have to be provided to the States under the JNNRUM and AMRUT programs.

21) a) To take up special program for minor irrigation works and mechanisation of agriculture/farming in drought prone areas (Vardha and Yavatmal districts of Maharashtra).

b) To take special development work programs in Naxalite infested areas. Infrastructure development is the best antidote to the growth of Naxalism.

c) To take special economic activities in highly underdeveloped districts like Kalahandi and Saputara districts in Odisha and Gujarat states respectively.

d) To launch a strong campaign for controlling adulteration of food stuffs, milk products and medicines. Adulteration of food-stuffs has became a very serious health hazard requiring urgent attention and follow up action.

A wave of infrastructure development has not been developed so far and people at large feel that the country is not moving ahead with desired speed. Accordingly the press is rightly calling 2016 as the Make or Break year for the government. Prime Minister of a country is the second God for his people because their destinies are gripped in his hands.

The country will not progress much till the government implements this basic 21 point program aggressively. Now NITI Ayog should be asked to formulate a

20 or 30-point national program for economic development on the above lines. Still 36 months are left for the Government to work professionally to make a turnaround in the fortunes of the country. The aspirational and transactional youth will not wait for the promised Achhe Din indefinitely. It is generally said that India will progress by leaps and bounds only if politicians start thinking of the nation as much as they think about their own future and future of their parties.

There are four PSU's which have been able to weave great success stories around them. These are ISRO, DMRC, NHAI and CIL. The good governance requires that government should direct all other departments and PSU's to emulate the work culture of the four PSU's.

Time has come when NITI AYOG has to examine seriously how China became the second largest economy in the world after 1980 and how India can replicate this example democratically over a period of next ten years. The dream of zero poverty by 2025 or 2030 will be realised only when a fine tuned N-point program like the one outlined above is prepared and implemented on a war footing- the way China fought against poverty under Deng Xiao Ping in 1980 or Singapore under Lee Kuan Yiew. Only then the curse and blot of poverty will be removed from the face of India. It will be a holy war against poverty and any general /leader who wins this war will be the rightful clamant to Nobel Prize and a unique place in the history of India.

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 h'some 29/6'1" B.Tech, MBA. Wkg offr psu oil co. etc. 14 LPA. Father GM PSU Avoid: Dahiya, Kadian, Cont.: 7544004285
- SM4 Smart Jat boy 26/5'1 1" Grad. Vot. Job CAG. only son 10 LPA seeks b'ful girl. Avoid: Rana, Balhara, Hooda, Cont.: 9811452626
- SM4 h'some boy 28/5'10", B.Tech I IT Delhi MBA IIM, Sr. Mngr. MNC 35 Lpa., Fathr CL- I Ofcr own banglow. Cont.: 8871282115
- SM4 h'some Jat boy Oct. 87/5'8". Asst. Mngr. Govt. Bank in Del. Fthr in IAF seeks b'ful qlfd girl from Hr/Del/Chndg, Cont.: 8588933547
- SM4 B.Tech, MBA Tall h'some Jat 28/6'2" boy wkg. MNC, father Retd. ACP. well Edu. & Settld. S.Delhi bsd fmly seeks b'ful, tall, edu. & wkg. girl from good fmly background. Avoid: Dhankhar, Sangwan, Cont.: 9810221484
- SM4 Jat boy 24, 5'11" doing Ph.D., W.UP family. Prefer Net Qlfd. Hindi, English, History girl from educated and respectful family. Avoid: Malik, Chauhan, Cont.: 9813405615
- SM4 Qualified B.Tech Electrical (Delhi) wrkg. as Manager in Central PSU, Banglore DOB 3.9.82, 5'1" father/brother wrkg. in PSU. Avoid: Chahal, Dahiva, Cont.: 9873417121
- Jat Boy 30/5'10" M.Tech (IIT Kanpur). Working in Central Government (Ministry of P&NG), Annuval income 10 lacks, Contact : 9039131507
- Jat Boy 28/5'9" B. Tech, MBA, wkg in Gurgaon, 9 LPA Contact : 8430790697
- SM4 Jat Girl 23/5'3" M.B.A. Employed in MNC at Mumbai with Rs. 4.50 Lakh package PA. Father & Mother in Government job. Avoid Gotras: Mor, Nain, Gill. Cont.: 09872330397, 09915711451
- SM4 Jat Girl (DOB 18.10.84) 31.10/5'3" M.Com. Passed Computer Course. Avoid Gotras: Kadian, Malik, Khatri. Cont.: 09468089442
- SM4 Jat Girl (DOB18.8.88) 28/5'3.6" M.Sc (Math), B.Ed. Working in a reputed private School. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: : 09354839881
- SM4 Jat Girl (DOB 28.11.93) 22.10/5'1" B.A. from P.U. Chandigarh. Doing practice for Stenographer. Avoid Gotras: Beniwal, Segwal, Kadian, Kuhad, Kaliraman. Cont.: 08591887304
- SM4 for Jat Girl (DOB 26.11.89) 26.9/5'3" B.Tech. M.Tech. Working as P.O. in I.D.B.I. Bank. Mother Class I officer & father Retd. as class one officer. Avoid Gotras: Pannu, Gill, Dhull. Contract: 09416865888
- SM4 Jat Girl (DOB 04.08.90) 25.8/5'4.5" M.Sc. from P.U. Chandigarh. Employed as Software Developer (Alchemist IT Company Chandigarh) Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar. Cont.: 09463330394
- SM4 Jat Girl (DOB 29.02.92) 24.2/5'4" M.Sc. Physics from P.U. Chandigarh. Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar. Cont.: 09463330394, 09646712812
- SM4 Jat Girl (DOB 04.11.90) 25.9/5'2" B.A. B.Ed. Employed as Officer in Haryana government. Avoid Gotras: Hooda, Kundu, Bhanwala. Cont.: : 09729235545
- SM4 Jat Girl (DOB13.09.87) 28.10/5'5" M.Tech. Employed as Lecturer in a reputed College at Sampla, Distt. Rohtak (Haryana) Avoid Gotras: Pawaria, Nandal, Ahlawat. Cont.: 09996060345
- SM4 Jat Girl 27.5/5'7" B.A. (Hons.) MA English, M.Phill. B.Ed. NET qualified Employed as J.B.T.Teacher in U.T. Chandigarh. Avoid Gotras: Malhan, Kadian, Chahar. Cont.: 09467394303
- SM4 Jat Girl (DOB 05.09.91) 24.10/5'6" M.Tech (CSE) Employed in a University. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Rana. Cont.: 07696844991, 07814609118
- SM4 Jat Girl (DOB 20.09.91) 25/5'6" M.Tech (ESE). Avoid Gotras: Panwar, Deswal, Ahlawat. Cont.: 08053825053
- SM4 Jat Girl (DOB 07.02.90) 25/5'10" B.Tech. (ESE) M.Tech (ESE) from M.D.U. Rohtak. GATE qualified. Avoid Gotras: Kadian, Rathee, Sangwan. Cont.: 08447796371
- SM4 wodow issue less Jat Girl (DOB 02.10.80) 35.5/5'3" MSc., M.Phill, B.Ed. Employed as Junior Lecturer in Haryana Government. Avoid Gotras: Nandal, Sehrawat, Dalal. Cont.: 08570032764
- SM4 Jat Boy (DOB 21.04.90) 25.6/5'9" B.Tech. Working as Assistant in Haryana Civil Secretariat in Excise & Taxation Deptt. Only son, Father and mother Gazetted Officers in Haryana government. Avoid Gotras: Mor,Siwach, Singroha.. Cont.: 09988701460
- SM4 Jat Boy 27/5'8" B.A., L.L.B. Practicising in District Court Panchkula. Avoid Gotras: Balyan, Nehra. Cont.: : 09996844340

Ch. Lajja Ram Malik -A Proud Jat

- Brig. K. Narendra Siva

Education is fundamental to human and social development. Due to lack of education the rural Haryana had failed to produce a Jat leader of stature though their kin in Punjab and Western U. P. had fared slightly better. Haryana Jars had been delegated to the back yard and were butt of crude jokes due to their simple rustic ways. Such was the scenario at the turn of the nineteenth century. There was abject poverty among the peasantry because of dependence was on rain fed subsistence farming. The dependence on the moneylender was often unavoidable at the cost of bartering away the land and personal dignity.

In the relatively prosperous khadar of river Yamuna there lived in village Ugarkheri near Panipat, a simple farmer named Budh Ram Malik. In the year 1880 on Diwali day, a son was born to his wife Raj Rani, a pious lady ofmuch charm and beauty. The old saying- "Maa Pai Poot Pita Pai Ghoda, ziada nahin tau thora thora" proved right and fearing the evil eye of the beholders, they named the child'Laj ja Ram',

that is, legacy of Lord Ram. Time proved that the child was gifted with good brawn and brain.

In the absence of a high school in the entire district, Laj ja Ram joined a Mission School in Delhi. There are two other bright Jat boys, Chhotu Ram and Lal Chand, who joined him later. The trio was in the forefront both in studies and games. On passing the high school, they joined St. Stephens Mission College, as it was called then. Chhotu Ram, one day, unable to bear the expenses, quietly left the college. Lajja Ram rushed to his village and brought him back on the assurance that together they will manage the expenses. Thus, early in his life Lajja Ram rendered an outstanding service to the community, and to the country as Chhotu Ram in the later years, rendered very significant services to the rural farming communities in the then Punjab State as a minister by binding them in secular bonds and by saving their lands from the money lenders.

Chhotu Ram and Lal Chand pursued their studies in Law. They realized that the political leadership was in the hands ofthose who were endowed with knowledge of Law. However, Lajja Ram was anxious to get on with his mission to wipe out the stigma attached to his tribe due to their inter and intra family feuds, indebtedness due to unnecessary expenses on marriage and funerals, ignorance about progressive ways in farming, keeping aloof from the progressive elements in the society and shunning education. In Government Service, as revenue collector, registrar and magistrate, he was poised to help his rural brethren by cajoling them and where necessary pushing them to regain their place of prestige by adopting progressive ways.

Being the only graduate Tehsildar with a refined taste in dress and a strong commitment for rural uplift, superiors like FL Brayne, ICS, up his name for up- gradation prestigious PCS cadre, but Ch. Lajja Ram spurned this offer with the desire to live in close touch with the rural communities On graduation, Dharm Singh, his only progeny, a joined as Tehsildar and the DEO father and son plunged theni selves in their mission.

Here ends the account of a proud Jat who gave his life liar for the emancipation of the Jat conununity From his vast library, the only book that has survived the onslaught of time is a 1896 edition of' Selections from'Steele's contribution to the TATLER'. He was a humble serevent of the community, who advocated 'Khak Sho Pesh Azan Keh Khak Shawi'- meaning-'Be humble like dust in your lifetime before you become dust after death'.

बेटी की पुकार

- प्रशून जोशी

शर्म आ रही है ना उस समाज को
जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया
शर्म आ रही है ना उस पिता को
उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया
शर्म आ रही है ना उन रस्मों को उन रिवाजों को
उन बेड़ियों को उन दरवाजों को शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को
जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा
शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को उन लिबासों को
जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा
शर्म आ रही है ना स्कूलों को दफ्तरों को रास्तों को मंजिलों को
शर्म आ रही है ना उन शब्दों को उन गीतों को
जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा
शर्म आ रही ना राजनीति को धर्म को
जहाँ बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न
शर्म आ रही है ना खब्बरों को मिसालों को दीवारों को भालों को
शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को
जिसने पंख काटे थे उसके
शर्म आनी चाहिए ऐसे हर खब्याल को
जिसने उसे रोका था आसमान की तरफ देखने से
शर्म आनी चाहिए शायद हम सबको क्योंकि
जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी
तब हम उसकी उँगलियों से छलकती रोशनी नहीं उसका लड़की
होना देख रहे थे
उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल और सब देख रहे थे मटमैला
आज
पर सूरज को तो धूप खिलाना था
बेटी को तो सवेरा लाना था
और सुबह हो कर रही

स्किल इंडिया के लिये शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता

- अनामिका

आज दिल्ली व अन्य बड़े शहरों से लेकर हमारे कस्बो–गांव तक शिक्षा संस्थानों की कमी नहीं है, पर क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि देश के चंद आईआईटी, आईआईएम, इनके समकक्ष संस्थानों और कुछ प्रावेट कॉलेजों को छोड़कर बाकी में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों हैं? आखिर क्यों हमारे ज्यादातर शिक्षा संस्थानों का मुख्य जोर सिर्फ परीक्षा पास करने पर होता है, बनिस्पत स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ाने और उन्हें नौकरी के लिए हुनरमंद बनाने के। यह अलग बात है कि बचपन से ही प्रतिभाशाली रहने वाले बच्चे गुड्डी के लाल की तरह अपनी अलग राह बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बेरोजगारी की विकराल समस्या से परेशान रहने के बावजूद हमारी सरकार और संस्थानों ने इसे दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं? क्या वे पूरी तरह कारगार हैं? या फिर वे सिर्फ नीतियों तक ही सीमित होकर रह गए हैं? आखिर जब हमारी इंडस्ट्री बार–बार यह कहती रही है कि उन्हें पर्याप्त संख्या में काबिल लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम उनकी बात पर गंभीरता से क्यों नहीं विचार करते और उचित कदम उठाते? जब कुछ निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान सिर्फ अपनी पहल पर अच्छा रिजल्ट देने के साथ–साथ अपने स्टूडेंट्स को आकर्षक नौकरी की राह सुलभ कराने में सफल हो रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों तमाम संस्थान क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने की बजाय आकर्षक विज्ञापनों के जरिये स्टूडेंट्स को बेककूफ बनाकर उनसे मोटी फीस वसूलने में लगे हुए हैं? नियामक संस्थाएं क्यों नहीं ऐसे संस्थानों की नकेल कसतीं? कहीं करप्शन का कीड़ा इन संस्थानों के जरिये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी तो खिलवाड़ नहीं कर रहा है?

केंद्र और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए संबंधित नियामक संस्थाओं के जरिये समयानुकूल करिकुलम बनवाकर उस पर कड़ाई से अमल कराएं। साथ ही, गुणवत्तायुक्त शिक्षा (प्रोफेशनल और नॉन–प्रोफेशनल दोनों) के लिए नियमित रूप से शिक्षा संस्थानों की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने और स्किल इंडिया की राह पर आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि थ्योरी के साथ–साथ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए। जहां प्रोफेशनल कोर्स हों, वहां आखिरी साल में इंडस्ट्री के साथ नियमित इंटरैक्शन अनिवार्य कर दिया जाए। इससे फायदा यह होगा कि उन स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से आउटपुट देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ऐसे स्किल्ड स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री भी तत्परता से अपनाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ऐसा होगा।

कैसे मिले गुणात्मक शिक्षा?

वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डालें, तो दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी या इसके समकक्ष संस्थान शामिल नहीं हैं। 200 से ऊपर के संस्थानों की वर्ल्ड रैंकिंग में भी सिर्फ 11 संस्थान (आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और इनके समकक्ष) हैं, जिनमें देश के महज 12 फीसदी स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिल पाता है। वहीं, हायर एजुकेशन के लिए हर साल करीब 3 लाख से अधिक स्टूडेंट अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों का रूख करते हैं यह तब है, जब मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे शहरों, कस्बों तक में हर साल नये–नये संस्थान खुलते जा रहे हैं, लेकिन विश्वस्तरीय क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने में खास रूचि न होने के कारण ज्यादातर संस्थान अपने फायदे के लिए शिक्षा बेचने वाली दुकान साबित होकर रह गए हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, नियामक, शिक्षा बोर्ड, परिषद वीसी, कॉलेज प्रबंधन या फैकल्टी/टीचर या फिर ये सभी?

दर्द

- पूनम सिंह

जिंदगी में होता है क्यू ऐसा
जिसे चाहें, वही दर्द दे हमेशा
शायद
एक वो ही है जो...
नजरों के है करीब
पढ़ सकता है उनकी मजबूरी
झांक सकता है दिल में
समझ सकता है उसकी कमजोरी
उतर सकता है रूह में
जान सकता है उसकी लाचारी
वरना तो कई मिलते हैं
जिन्दगी की राहों में
दिल को दर्द देना तो दुर
ठहर तक नहीं पाते निगाहों में।

जीवन में सफलता हेतु आत्मविश्वास से जुड़े 10 आसान रास्ते

- अनामिका

जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी यदि कुछ है तो वह है आपका आत्मविश्वास। आपने अलग–अलग फील्ड के कामयाब लोगों से बात करते हुए पाया होगा कि उनका आत्मविश्वास कमाल का है। यही आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ने और कुछ करने की प्रेरणा देता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा तजुर्बा क्या है, हमारा इतिहास क्या है... यह सब भूल जाइए, याद रखिए तो सिर्फ इतना कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। अर्थात आप वर्तमान में रहें। अकसर हम यह सोचते हैं कि कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि हम पहले भी कामयाब रहे हों... इससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन वर्तमान में रहकर अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना और अपनी क्षमताओं को पूरा विस्तार देना कामयाबी की नींव तय करती है।

यहां कुछ 10 तरीकों का जिक्र किया जा रहा है जिससे आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ सकेंगे और वह है आपका अपना आत्मविश्वास...

1. पहली बात तो यह ध्यान रखने की है कि आत्मविश्वास व्यक्ति के भीतर से आता है, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है। किसी ओर के आत्मविश्वास में जलने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे लोग आपके तौर–तरीकों और आत्मविश्वास से सबक ले रहे हों। उन्हें आप पर भरोसा हो।

2. दूसरी जरूरी बात है कि आप अपना सबसे सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को सही से नहीं जानता वह दुनिया में किसी और को नहीं जान सकता है। इसलिए पहले अपने आप को और अपनी क्षमताओं को समझें, हो सके तो उनकी एक लिस्ट तैयार करें... हो सकता है कि पहले यह आपको कुछ अटपटा लगे... लेकिन अपने आपको पहचानने के लिए यह जरूरी है। यही काम आपको आगे अपने में सुधार के लिए भी प्रेरित करेगा।

3. याद करिए जब जब आपने आत्मविश्वास से जिंदगी में कुछ पाया हो। उन पलों को याद करिए जब आपने मुसीबत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो। यह कभी भी किया हो सकता है। हो सकता है बचपन में आप काफी सक्रिय रहे हों... उसे याद करिए... उस दौर को याद करिए जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने का मादा रखते हों... एक भी ऐसी पहल आपको आगे बढ़ने में सहायक का काम करेगा।

4. याद रखिए आत्मविश्वास गुणात्मक रूप से बढ़ता है। यदि आप में आत्मविश्वास जागा तो आप जो भी करेंगे आप बेहतर करेंगे। आप उन बातों के लिए भी उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे जिन्हें आपने पहले नहीं किया हो। आप अपना सही आंकलन कर सकेंगे और शायद यह आपकी कामयाबी का पहला कदम होगा।

5. सदा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें... यह दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी...। आपने देखा होगा, कि कामयाब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, बनी रहती है और जिसे लोग कामयाबी की चमक कहते हैं।

6. आप अपने एटिट्यूट के साथ ग्रैटिट्यूड की भावना भी रखें... यह भी एक कारगर उपाय है।

7. एक बात और... आत्मविश्वास के लिए हर आदमी का अपना अलग पैमाना होता है। आप अपने आत्मविश्वास की वजहों को पहचानों, उन्हें समझों और लिखो... फिर लिखो... आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं, जो वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। अब आप ऐसे मुकाम पर हैं जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कुछ नियम बना सकते हों... जो आपमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। ऐसा करने का एक नियम यह है कि ये या वो हो... ये ओर वो का नियम नहीं...

8. कभी–कभी ऐसा भी होता है कि आत्मविश्वास जगाने के लिए सबकुछ करने के बाद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाते... ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि अपने कुछ ऐसे दोस्तों, जानने वालों के साथ समय बिताएं जो आत्मविश्वासी हैं। इनमें भी यदि कोई ऐसा हो जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी सीधी मदद कर सके, तो सोने पर सुहागा...

आत्मविश्वास का एक नियम यह है कि माहौल बेहतर हो, तो तेजी से बढ़ता है... यानि आप आत्मविश्वासी लोगों के बीच रहोगे तो यह गुण अपने आप आपमें आ जाएगा।

9. एक और बात बहुत छोटी है, लेकिन सत्य है। आप कोई काम जब पूरा करते हैं, भले ही वह छोटा हो तो आत्मविश्वास को जगाता है। आप अपने चारों ओर देखिए... कई छोटे–छोटे काम हैं जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं... ये सभी आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

10. याद रखें... सिर्फ आप ही अपने आत्मविश्वास के मालिक हैं। आप ही आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। आप ही इसे मार सकते हैं। अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। भूल जाइए कि आपने अब तक क्या किया है... जरूरी यह नहीं कि आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, आवश्यक यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।

समय साथ न दे तो चुप रहने में ही भलाई है। सही समय आने पर कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं। –रहीम

श्रद्धा

नरेन्द्र आहूजा

मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। श्रद्धापूर्वक किए गए कार्चर्य ही सफल हो जाते है। मानव जीवन में श्रद्धा नींव की उस ईंट की भांति है जिस पर मनुष्य जीवन भवन का निर्माण करते समय धर्म कर्म और साधना की दीवारें खड़ी करता है। श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी उतना ही मजबूत जीवन का भवन होगा। छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है कि 'बिना श्रद्धा के मनन नहीं होता।' गीता में भी योगेश्वर कृष्ण ने श्रद्धा के महत्व को दर्शाते हुए कहा 'जो काम श्रद्धा से ना किया जाये, वह लोक परलोक में काम नहीं आता।' श्रद्धा मनुष्य को शक्ति `दती है, सद्प्रेरणा देती है और जीवन को सार्थक बनीती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते हैं जहां द्धछा है वहां पराजय नहीं होती। अल्पज्ञता के कारण संशय रूपी चूहा मानव मन में विश्वास के वस्त्र को कुतर कर श्रद्धा को समाप्त कर देता है। यदि मन में किसी विचार, सिद्धान्त या कार्य के प्रति संशय है तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार यदि श्रद्धा है तो संशय पास नहीं फटक सकती।

अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह श्रद्धा है क्या? श्रद्धा का अर्थ है – सत्य में धारणा। इस अर्थ का यदि हम और अधिक विस्तार से विमोचन करें तो ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। सार्वकालिक सार्वळौमिक अपरिवर्तनीय ही सत्य कहलाता है। ईश्वर एवं ईश्वरीय ज्ञान वेदादि शास्त्र सत्य हैं इन पर धारणा ही श्रद्धा कहलाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा सिद्धान्त विचार वा कार्य जो सत्य की श्रेणी में नहीं आता उस पर विश्वास करना श्रद्धा नहीं हो सकता। यिद हम ईश्वर के सही स्वरूप् को जाने बिना किसी पाखंड व अंधविश्वास के शिकार होकर तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत की जाने वाली असत्य बातों पर विश्वास करेंगे तो वह श्रद्धा की श्रेणी में नहीं आते। असत्य को मानना अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर चलना चाहिये। श्रद्धा जैसे दिव्य गुण से जहां मनुष्य सत्यस्वरू् परमपिता परमेश्वर को पाकर संसार के समस्त एश्वर्यो को भोगता हुआ शिखर पर पहुंचता वहीं अंधश्रद्धा मनुष्य को पतन की गहरी खाईयों में धकेल देती हैं।

यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया कि श्रद्धा सत्यामाप्यते। यजु० 19/30 अर्थात श्रद्धा से सत्यस्वरू् परमेश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य में धारणा विश्वास अर्थात श्रद्धापूर्वक ईश्वरीय सत्य ज्ञान वेदादि शास्त्रों के अनुकूल चलने से सत्यस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होती है। जीवन को श्रद्धा से ओत–प्रोत कर पूर्ण श्रद्धा से सत्यस्वरू् परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देने में ही कल्याण है। श्रद्धा विन्दते वसु। क्र० 10/151/14 अर्थात श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। सत्यस्वरूप ईश्वर एवं ईश्वरीय सत्य ज्ञान वेदादि शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा कल्याणकारी माता के समान रक्षा करती है।

मेरी बिटियां

राधा

मेरी बिटियां मिट्ठू नाम,
करती है कुछ ऐसे काम।
देख–देख कर हंसते सब,
वह शैतानी करती जब।
पप्पी के पप्पी लेती,
खाने को बिस्कुट देती।
डॉल, वॉल से रहती दूर,
पर मस्ती करती भरपूर।
फूल लगे फुलबारी में,
उसकी पहरेदारी में।

क्या मजाल छू ले कोई,
अगर छुआ समझो रोइ।
छादी–दादा उसकी जान,
हरपल रखती उनका ध्यान।
दूध कभी कॉफी लाती,
कूद–कूद कर पिलवाती।
मीठी बातें करती है,
रोती नहीं, मचलती है।
मम्मी–पापा की आंखों का नूर,
सभी प्यार करते भरपूर।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया ।